संसद के समक्ष अभिभाषण – 14 फरवरी 1966

लोक सभा	-	तीसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	सरदार हुकम सिंह

माननीय सदस्यगण,

एक बार फिर, संसद के नए सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। महीना भर हुआ राष्ट्र से उसके प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री छिन गए। वे निश्चय ही जन-साधारण थे और जन-साधारण से उनका संबंध निरन्तर बना रहा। साध्य की दृढ़ता को कायम रखते हुए वे यथावश्यक साधनों को अपनाते थे। वे स्वभाव से अत्यंत विनम्र, व्यवहार में सरल, वाणी में कोमल और शांति के पुजारी थे। संकट की घड़ियों में वे शान्त, उत्साही और अडिग बने रहते थे।

जिन घटनाचक्रों में पड़कर हमें पाकिस्तान के साथ सशस्त्र संघर्ष करना पड़ा, उनसे उन्हें बड़ा दु:ख था फिर भी उन्होंने राष्ट्र को प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान किया। हमारी वीर सेनाओं ने हमारे इतिहास में गौरव का एक नया अध्याय जोड़ दिया है। हम अपने वीरों का सम्मान करते हैं, शहीदों के लिए शोक मनाते हैं और उनके दु:खी संबंधियों को सान्त्वना देते हैं। भारत की जनता ने एक बार फिर अपनी एकता और संगठन का सबूत दिया। देश भर में सांप्रदायिक एकता बनी रही। हमारे मजदूरों ने भी अनोखा उत्साह दिखाया।

जब लड़ाई बंद हो गई तब लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शक्ति पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी के संबंध स्थापित करने की ओर लगाई। अपनी अचानक और असामयिक मृत्यु के पूर्व उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के साथ सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष

श्री कोसीगिन की उपस्थिति में ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए। श्री कोसीगिन की सद्भावना और मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण इस करार के संपन्न होने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुआ। लाल बहादुर शास्त्री को आशा तथा विश्वास था कि ताशकंद घोषणा से भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति और मित्रता की नींव पड़ेगी। ताशकंद घोषणा के शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण उसकी भावना है। दोनों पक्षों को आस्था और दूरदर्शिता के साथ उसका आदर करना है।

हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के प्रायः सभी देशों के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हैं। हमें इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि अपने पड़ोसियों के साथ हमारी समझ-बूझ अधिक बढ़ी है और मित्रता के संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। दुर्भाग्यवश, चीन लोक गणराज्य के साथ हमारे संबंधों में अब भी तनाव बना हुआ है। देश को होशियार रहना और मजबूत बनना है।

हमारी सरकार विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न करती रहेगी। शांति हमारे अपने विकास, प्रगति और हमारी सारी जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य से हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करेंगे। इस सहयोग के आधारभूत सिद्धांत होंगे—शांतिपूर्ण सहजीवन, दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, गुट-विमुक्ति जिसमें समस्याओं पर तथ्यानुसार निर्णय करने की स्वतंत्रता है और, उन सबसे बढ़कर, झगड़ों को तय करने में बल-प्रयोग का परित्याग। अगर खुशहाल राष्ट्रों के साधन, जिनका अपव्यय आज हथियार बनाने पर किया जा रहा है, मानवता की सेवा में लगाए जा सकते, तो दीनता और अज्ञानता में रहने वाले लोग अपने जीवन-काल में ही नई उपलब्धियों की आशा रख सकते थे।

एशिया और अफ्रीका के देश, जो उपनिवेशवादी आधिपत्य में थे, एक के बाद एक, स्वतंत्र हुए हैं और उन्होंने राष्ट्रों के समुदाय में अपना समुचित स्थान प्राप्त किया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ देश अब भी पुर्तगालियों के आधिपत्य में हैं, और हमारी सहानुभूति उनके साथ है जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में वर्णभेद के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं।

रोडेशिया द्वारा स्वाधीनता की एकतरफा घोषणा और अल्पसंख्यक जाति का बल द्वारा सत्ता को अपने हाथ में लेना, जो रोडेशिया की जनता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है—यह एक बहुत दुःखद घटना है। हमने रोडेशिया के साथ राजनयिक, आर्थिक सब तरह के संबंध तोड़ दिए हैं और एक सच्ची प्रजातंत्रात्मक सरकार स्थापित करने में हम रोडेशिया की जनता का पूरी तरह समर्थन करते रहेंगे।

वियतनाम की वर्तमान स्थिति पर हमें गंभीर चिंता है। हमारा समर्थन किसी भी ऐसे प्रयत्न के साथ होगा, जिससे यह संघर्ष शांतिपूर्ण उपायों से समाप्त किया जा सके।

गत वर्ष मैंने यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और इथियोपिया की यात्रा की। इन सब देशों में मेरा हार्दिक स्वागत किया गया और भारत और उसकी जनता के प्रति सद्भावना और घनिष्ठ मैत्री के मुझे सबूत मिले। उपराष्ट्रपति ने कुवैत, सउदी अरब, जॉर्डन, टर्की और ग्रीस की यात्रा की, जहां पर उनका बहुत खलूस और मित्रता से स्वागत किया गया। वही मित्रता की भावना नेपाल, सोवियत संघ, संयुक्त अरब गणराज्य, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, यूगोस्लाविया और बर्मा* की जनता और सरकार में देखी गई जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री शास्त्री जी ने इन देशों की यात्रा की। हमें भी नेपाल के महाराज और महारानी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, अफगानिस्तान, चेकोस्लोवाकिया, लाओस और उगांडा के प्रधान मंत्रियों तथा संसार के विभिन्न देशों के बहुत से विशिष्ट व्यक्तियों का अपने देश में स्वागत करने का सुअवसर मिला। लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए पिछले महीने बहुत-सी सरकारों के अध्यक्ष और अन्य महानुभाव दिल्ली आए और उनकी उपस्थिति से हमें बड़ी सान्त्वना मिली।

1965-66 हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है। हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि जो योजना के पहले दो वर्षों में मंद थी, अब गतिमय होकर तीसरे वर्ष में 4.5 प्रतिशत और चौथे वर्ष में 7.3 प्रतिशत तक पहुंच गई है। सामान्य परिस्थितियों में यह संभव होना चाहिए था कि चालू वर्ष में भी तुलनात्मक वृद्धि की यह दर कायम रखी जाती। दुर्भाग्यवश, कई प्रतिकूल बातों से उत्पादन की गति मंद हो गई है। वर्षा की बेहद कमी, सशस्त्र संघर्ष जिसमें देश को उलझना पड़ा और बाहर से मिलने वाली आर्थिक सहायता को रोक दिया जाना—इन सबने हमारी वृद्धि की दर को घटा दिया है।

समय पर वर्षा न होने के कारण ऐसी आशंका है कि 1965-66 में खाद्यान्नों की पैदावार सिर्फ 760 से 770 लाख टन होगी जबकि पिछले वर्ष 880 लाख टन हुई थी। खाद्यान्नों की कमी के कारण, साथ ही चरी और पानी की कमी के कारण भी, बहुत से प्रदेशों में सूखे की हालत आ पहुंची है, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। सूखे से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें कदम उठा चुकी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, और विभिन्न मित्र देशों की सरकारों और जनता ने जो हमें तुरन्त सहायता दी है उसके लिए हम इस अवसर पर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। विशेषरूप से, हम संयुक्त राज्य अमेरीका के राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे जिन्होंने इस आड़े समय में उदारतापूर्वक हमारी सहायता की।

ऐसे उपाय बरतने पड़ेंगे जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त सामग्री में से हर मनुष्य और हर राज्य को उसका समुचित हिस्सा मिल सके। कानूनी राशनिंग कलकत्ता[@], मद्रास[#], कोयम्बटूर और दिल्ली में शुरू कर दी गई है। आगामी महीनों में कई अन्य नगरों में भी शुरू की जाएगी।

* अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।
@ अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।
# अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।

केरल में जो कठिनाई अनुभव की जा रही है उससे सरकार अवगत है। चावल की उपलब्धि से वहां प्रति व्यक्ति को केवल 140 ग्राम रोजाना राशन दिया जा सकता है। उसे उतने ही गेहूं से पूरा किया जा रहा है। चावल कम मिलने के कारण वहां पिछले दिनों बड़ा असंतोष रहा और आंदोलन हुआ। बाहर से आयात करके और देश से अतिरिक्त राशि प्राप्त करके अधिक चावल देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि जिन प्रदेशों में अधिकता है, वे केरल के लोगों को ज्यादा चावल उपलब्ध कराने में पूरी तरह सहयोग देंगे।

हमारी वर्तमान कठिनाइयां ऐसे साधनों को एकत्र करने और उनके प्रयोग करने की आवश्यकता पर एक बार फिर बल देती हैं जिनसे कम-से-कम समय में खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाई जा सके। केवल आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विद्या की सहायता से ही हम अपनी खेती की पैदावार पर्याप्त मात्रा में बढ़ा सकते हैं। हमारी सरकार के कृषि-संबंधी नए उपायों में सबसे अधिक बल सुधरे किस्म के बीजों के प्रयोग पर दिया जाता है जिन पर उर्वरकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। 1966-67 तक पैंतालीस लाख एकड़ जमीन के लिए देश में उर्वरकों की पैदावार बढ़ाई जा रही है। ट्राम्बे फर्टिलाइजर प्लांट चालू हो चुका है और नैवेली प्लांट निकट भविष्य में उत्पादन आरंभ कर देगा। 1967 में नामरूप, गोरखपुर, बड़ौदा और विशाखापट्टनम में चार प्लांट लगाए जाएंगे। इस क्षेत्र में लगाने के लिए, देशी और विदेशी निजी पूंजी को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में कुछ निर्णय किए गए हैं। जब तक देशी उत्पादन पर्याप्त नहीं होता तब तक सरकार अपने कृषि कार्यक्रम के लिए वांछित मात्रा में उर्वरकों का आयात करना चाहती है।

सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। ऐसा अनुमान है कि आगामी वित्तीय वर्ष में बड़ी और मंझली सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 30 लाख एकड़ जमीन के लिए पानी मिल सकेगा। छोटी सिंचाई परियोजनाओं की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। चौथी योजना के दौरान, ऐसी आशा की जाती है कि लगभग 7 लाख पंपिंग सेट चालू कर दिए जाएंगे। गांव में बिजली पहुंचाने पर काफी जोर दिया जाएगा।

हमारी सिंचाई योजना से पानी और उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने के लिए काश्तकार को धन की आवश्यकता होगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि काश्तकार को उधार धन जल्दी मिल सके और अपेक्षाकृत कम ब्याज की दर पर।

खेती-बाड़ी को जो हम ऊंचे दर्जे की प्राथमिकता दे रहे हैं वह केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि उससे हमारी अनाज संबंधी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सकेगी, बल्कि इसलिए भी कि उससे हम कृषि और औद्योगिक उत्पादन का अपना निर्यात बढ़ाने में भी समर्थ हो सकेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में हमारे निर्यात में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई। लेकिन पिछले दो वर्षों में हमारा निर्यात प्रायः

जहां का तहां रहा है। पूर्व यूरोपीय देशों में सामान्य रूप से, और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से विशेष रूप से, हमारा निर्यात काफी बढ़ा है। तो भी, दुनिया के शेष देशों के साथ लेन-देन की स्थिति हम पर बोझ बनी हुई है। देश के विकास में बाहरी सहायता से वांछित योगदान मिलता रहा है और हम उन बहुत से देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति आभारी हैं जिनसे हमें सहायता मिलती है, फिर भी, जितनी जल्दी हो सके हमें निर्यात बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी लगन से जुट जाना चाहिए।

सरकारी सैक्टर के कई संयंत्रों ने कुछ समय हुआ उत्पादन आरंभ कर दिया है। मशीन बनाने वाले, तेल शोधन वाले, और एलॉय स्टील का उत्पादन करने वाले सैक्टरों की क्षमता और बढ़ी है। चौथी योजना में सरकारी सैक्टर में उद्योगों के विस्तार के लिए पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय है, बोकारो का स्टील प्लांट जो सोवियत सहयोग से खड़ा किया जाएगा और वे कारखाने जिनका उद्देश्य है परमाणु शक्ति को शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्यों के लिए नियोजित करना। डॉ. एच.जे. भाभा की दु:खद मृत्यु से एटॉमिक एनर्जी कमीशन और वस्तुत: विज्ञान संसार को क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना असंभव है। जो काम उन्होंने आरंभ किया था उसे अबाध गति से आगे बढ़ाना चाहिये।

सरकारी सैक्टर में जो पूंजी हम लगाते हैं उसका पर्याप्त लाभ हमें मिलना चाहिये। हमारी सरकार का इरादा है कि वह सरकारी सैक्टर के कारखानों के दक्षतापूर्ण प्रबन्ध की ओर विशेष ध्यान दे।

निजी सैक्टर के उद्योगों को भी अपना उत्पादन और क्षमता बढ़ानी है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और तंगी की हालत में कुछ कटौतियां और नियंत्रण अनिवार्य हैं, फिर भी ऐसी स्थितियां लाई जानी चाहिएं जिनमें चौथी पंचवर्षीय योजना के ढांचे के भीतर निजी पहलकदमी और निजी बचत, वृद्धि और विकास के हित में ज्यादा से ज्यादा काम आ सके।

अपनी जनता का स्वास्थ्य सुधारने और जीवनावधि की औसत बढ़ाने में हमने जो सफलता प्राप्त की है उससे हमें संतोष है। इस समय उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या लगभग 90,000 है जबकि 1960-61 में यह संख्या 70,000 थी, और इस अवधि में अस्पताली बिस्तरों की संख्या लगभग एक तिहाई बढ़ गई है। पिछले दशक में मलेरिया से होने वाली मृत्यु पर प्राय: पूरी तरह काबू पा लिया गया है। मृत्यु की दर में कमी लाने के साथ-साथ हमें पैदायश की दर भी घटानी पड़ेगी। अगर आबादी लगभग दस लाख प्रति मास की दर से बढ़ती गई तो हमें अपने जीवन-स्तर को ऊंचा करना और अपनी जनता का पेट भरने के लिए आयात पर लगातार निर्भर होने से बचना कठिन हो जाएगा। परिवार परिसीमन के कार्यक्रम को तेजी से चलाना है और सबको इससे परिचित कराना है।

प्राइमरी दर्जे पर स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या जो प्रथम योजना के आरंभ में 40 प्रतिशत से कुछ अधिक थी, इस वर्ष लगभग 80 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि में उच्च दर्जों पर प्रतिशत लगभग तिगुणा हो गया है। तीसरी योजना के दौरान टैक्नीकल ट्रेनिंग संस्थाओं के स्नातकों की संख्या दुगनी हो गई है।

साल के दौरान कीमतें बराबर बढ़ती रहीं, तो बढ़ोतरी की दर इतनी ऊंची नहीं थी जितनी पिछले साल। इस वर्ष कृषि उत्पादन में जो गिरावट आई है उसे ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्फीति संबंधी दबाव पर नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाना जरूरी हो गया है। सरकारी खर्च में कटौती करने से इस संबंध में काफी असर हो सकता है।

हमारी सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि योजना के बाहर के खर्चों में कुछ काट-छांट करे और अपने संसाधनों को विकास पर केन्द्रित करे। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अधिक खर्च करना ही पड़ेगा। हमें उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी है जो हाल के संघर्ष में विस्थापित हो गए हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हमें राहत पहुंचाने के उपाय करने ही हैं। हाल के महीनों में हमारी उत्तरी सीमा पर जो तनाव बढ़ा है उसके कारण सुरक्षा पर अधिक व्यय की व्यवस्था करने को हम बाध्य हैं। जैसी परिस्थितियां हैं उनमें अधिक कठोर आर्थिक अनुशासन अनिवार्य है, जो भीतर भी लागू हो और बाहर भी।

धन संबंधी और आर्थिक नियंत्रण, भले ही वे थोड़े समय के लिए आवश्यक जान पड़े, हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकते। गरीबी को हटाने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकारी सेक्टर और निजी सेक्टर को भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं।

किन्हीं कारणों से जिनका गुमान नहीं था, चौथी योजना की तैयारी में दुर्भाग्यवश विलंब हो गया है। 1966-67 के लिए योजना तैयार है, इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारें अपने संसाधनों को एकत्र कर रही हैं। यद्यपि 1966-67 की योजना पर होने वाला कुल खर्च उससे कम रहेगा जिसकी हमने आशा की थी, फिर भी इस बात के लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि इस कमी को चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में पूरा कर दिया जाए।

माननीय सदस्यगण, एक नई सरकार सत्तारूढ़ हुई है। इसका नेतृत्व एक ऐसी हस्ती के हाथ में है, जिसे आप सब जानते हैं, और जो आजादी के सैनिकों में युवा पीढ़ी की है। विभागों और मंत्रालयों के पुनर्गठन में वह प्राथमिकता प्रतिबिंबित है जिसकी ओर मैंने अभी संकेत किया है।

आपके विचारार्थ आपके सामने 38 बिल पहले से हैं। जो नए बिल सरकार आपके सामने रखना चाहती है, उनमें से कुछ ये हैं–

(1) चावल-शोधक उद्योग (विनियम) संशोधन बिल, 1966;

(2) फसल बीमा बिल, 1966;

(3) भारतीय तटकर (संशोधन) बिल, 1966 (ऑर्डिनेंस की जगह);

(4) आवश्यक व्यापार वस्तु (संशोधन) बिल, 1966;

(5) ठेका मजदूर (नियमन और समाप्ति) बिल, 1966;

(6) अग्रिम ठेका (विनियम) संशोधन बिल, 1966;

(7) सशस्त्र सेना (विशेषाधिकारों की बरकरारी) बिल, 1966; और

(8) आयात-निर्यात नियंत्रण (संशोधन) बिल, 1966।

1966-67 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के अनुमानित आय-व्यय का एक ब्यौरा आपके सामने रखा जाएगा।

माननीय सदस्यगण, मेरी शुभकामना है कि आप अपने कार्यों में सफल हों। हमारा उद्देश्य विदित और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हमें देश में अपनी जनता के जीवन की बेहतरी के लिए प्रयत्न करना, और विश्व में शांति और सहयोग को समुन्नत करने के लिए सहायता प्रदान करना है। उन लक्ष्यों की ओर साहस, बुद्धि और सहकारिता की भावना से आपको अपने देश को ले चलना है।